



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]
No. 366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 1980/कार्तिक 30, 1902
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 1980/KARTIKA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाले जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह अंतरालमध्य

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1980

“(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक, विलीन राजपत्र में प्रधिसूचना द्वारा, नियन करे।”

2. भारा 2 में,—

(क) विद्यमान खण्ड (क) को उसके खण्ड (ख) के रूप में पुनः प्रकाशित किया जाएगा और इस प्रकार खण्ड को पुनः प्रकाशित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया विलीन संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करते हुए, अपर्याप्त है;

(ख) विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ग) “प्रशासन प्राधिकारी” से विलीन पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का केन्द्रीय प्रधिनियम 34) की भारा 146 के साथ पठित चलचित्र प्रधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय प्रधिनियम 37) की भारा 11 के

उपाय

1. भारा 1 में,—

(क) उपधारा 2 में, “हरियाणा राज्य” शब्दों के स्थान पर “दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अपर्याप्त :—

प्रश्न विलीन में अनुज्ञाप्तियों को मंजूरी देने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी प्रभिन्नत है।

“अनुज्ञाप्तिधारी” से ऐसा व्यक्ति प्रभिन्नत है जिसे चलचित्र

(प) प्रधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय प्रधिनियम 37) की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञाप्ति मंजूर की गई है;

(ग) विद्यमान छाण्ड (ध) को उसके छाण्ड (क) के रूप में पुनः प्रकारांकित किया जाएगा।

3. धारा 3 से 7 का (बोनों की सम्मिलित करते हुए) लोप किया जाएगा।

4. धारा 7-क की उपधारा (4) में, “मरकार” शब्द के स्थान पर उम बोनों स्थानों पर जहां वह आता है, “प्रशासक” शब्द रखा जाएगा।

5. धारा 7-क में, “मरकार” शब्द के स्थान पर “प्रशासक” और “कर सकेगा” शब्दों के स्थान पर “कर सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 7-ग में, “दण्ड प्रक्रिया” संहिता, 1898” शब्दों और इनकों के स्थान पर “दण्ड प्रक्रिया, संहिता, 1973 (1974 का 2)” शब्द, इनकों और “कोल्डक रखे जाएंगे।

7. धारा 8 और 8-क का लोप किया जाएगा।

8. धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, प्रथात् :—

“9. नियम बनाने की शक्ति—प्रशासक, विलीन राजपत्र में प्रधिसूचना द्वारा, वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए धारा 7-क की उपधारा (4) के अधीन अपील की जा सकेगी, विहित करते हुए नियम बना सकेगा।”

9. धारा 10 और 11 का लोप किया जाएगा।

पंजाब सिनेमा (विनियमन) प्रधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब प्रधिनियम सं० 11) जैसा कि वह हरियाणा राज्य में प्रयुक्त है, जैसा कि उस का विलीन संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है।

उपांत्य

पंजाब में चलचित्रों के प्रदर्शन को विनियमित करने का उपबंध करने के लिए प्रधिनियम

यह निम्नलिखित रूप में प्रधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) इस प्रधिनियम का नाम पंजाब सिनेमा (विनियमन) प्रधिनियम, 1952 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण विलीन संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह उस सारी शब्दों को प्रयुक्त होगा जिसे प्रशासक, विलीन राजपत्र में प्रधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ.—इस प्रधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा व्यापक न हो,—

(क) “प्रशासक” से संबिधान के मनुष्योद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया विलीन संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिन्नत है;

(ख) “चलचित्र” के अंतर्गत शब्दों या विद्यावलियों का प्रदर्शन करने वाला साधिक भी है;

(ग) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से विलीन पुलिस प्रधिनियम, 1978 (1978 का केन्द्रीय प्रधिनियम 34) की धारा 146 के साथ पठित चलचित्र प्रधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय प्रधिनियम 37) की धारा 11 के अधीन विलीन में अनुज्ञाप्तियों की मंजूरी देने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी अभिन्नत है;

(घ) “अनुज्ञाप्तिधारी” से ऐसा व्यक्ति प्रभिन्नत है जिसे चलचित्र प्रधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय प्रधिनियम 37) की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञाप्ति मंजूर की गई है;

(ङ) “विहित” से इस प्रधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित प्रभिन्नत है।

* * * * *

धारा 3 से 7 का लोप किया गया

* * * * *

7-क. अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा सीटों के वर्गीकरण और प्रवेश की दरों में संशोधन या परिवर्तन (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित चलचित्र के प्रदर्शन के लिए सीटों के वर्गीकरण और प्रवेश की दरों का पालन करेगा और उनमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के लियित अनुमोदन के बिना संशोधन या परिवर्तन नहीं करेगा।

(2) यदि अनुज्ञाप्तिधारी चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की दरों में वृद्धि करना चाहता है तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसके लिए कारणों का कथन करते हुए, उस तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व, जिसको ऐसी दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, लिखित आवेदन करेगा।

(3) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की दरों में वृद्धि, चलचित्र प्रदर्शन की टिकटों के क्रेता पर अनुकूल रूप से प्रभाव नहीं ढाकेंगी तो, वह कारणों को अभिलिखित करके, ऐसी वृद्धि का प्राप्तिवान कर सकेगा :

परन्तु ऐसा अनुमोदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार से अधिक नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के विनियम से अधित कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रशासक को अपील कर सकेगा और प्रशासक, उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

7-क. प्रशासक की चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की दरों में संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति.—यदि प्रशासक की वह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आवेदन द्वारा कारणों की अभिलिखित करके चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की दरों में संशोधन या परिवर्तन कर सकेगा और अनुज्ञाप्तिधारी ऐसा आवेदन का तदनुसार पालन करेगा।

7-क. प्रशासक की विकाय के लिए सास्ति और अपराधों का संज्ञान, (1) केन्द्रीय सुखाचार प्रधिनियम, 1882 की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की टिकट का क्रेता द्वारा लाभ के लिए पुनः विकाय की विकाय होनी किया जाएगा।

(2) जो कोई चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रवेश की किसी टिकट का सामग्री के लिए पुनः विकाय करेगा, वह ऐसे जुर्माने से जो दो सौ रुपए हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई अपराध उस संदित्ता के अर्थ में संशेय माना जाएगा।

* * * * *

(धारा 8 और 8-क—लोप किया गया)

9. नियम बनाने की शक्ति.—प्रशासक, विलीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए धारा

public interest, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, amend or alter the rates for admission to the cinematograph exhibition and the licensee shall comply with such order accordingly.

7C. Penalty for resale of tickets and cognizance of offences.—(1) Notwithstanding anything contained in section 56 of the Indian Easements Act, 1882, a ticket for admission to a cinematograph exhibition shall not be resold for profit by the purchaser thereof.

(2) Whoever re-sells any ticket for admission to a cinematograph exhibition for profit shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), an offence

under this section shall be deemed to be cognizable within the meaning of that Code.

*** *** ***

Sections 8 and 8A—omitted.

9. Power to make rules.—The Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, make rules prescribing the time within which and the conditions subject to which an appeal under sub-section (4) of section 7A may be preferred.

*** *** ***

Sections 10 and 11—omitted.

[No. U-11015/1/80-UTL-(149)]

R. V. PILLAI, Jt. Secy.